भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 345
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पंजीकृत मछुआरा परिवार

345. श्री मुरसोली एस.:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के तंजावुर जिले में पंजीकृत मछुआरा परिवारों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत कितनी सहायता राशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कावेरी नदी प्रणाली पर निर्भर अंतर्देशीय मछुआरों ने पानी के कम प्रवाह के कारण मछलियों को पकड़ने में कमी आने की बात कही है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डेल्टा जिलों में वैकल्पिक आजीविका के रूप में अंतर्देशीय जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) तमिलनाडु सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जिला मत्स्य किसान विकास एजेंसी (DFFDA) के पास कुल 1,480 अंतर्देशीय मत्स्य किसान पंजीकृत हैं तथा अंतर्देशीय मछुआरा सहकारी समितियों में कुल 1,234 अंतर्देशीय मछुआरे पंजीकृत हैं; विगत तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 196.30 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है, जिनमें ताजे पानी की फिनफिश हैचरी का निर्माण (2 इकाइयां), सीड रेयरिंग तालाबों का निर्माण (07 हेक्टेयर), नए ग्रो आउट पॉन्ड्स का निर्माण और इनपुट सहायता (25 हेक्टेयर), संवर्धन तालाबों के लिए इनपुट सब्सिडी सहायता (25 हेक्टेयर), लघु बायोफ्लॉक इकाइयों की स्थापना (09 इकाइयां) तथा री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (01 इकाई) की स्थापना शामिल है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी क्षेत्र में एक अध्ययन संचालित किया है; इस अध्ययन से पता चला है कि एक सुविकसित नहर नेटवर्क के माध्यम से कृषि प्रयोजनों के लिए नदी के पानी के व्यापक डायवर्जन (मार्ग परिवर्तन) के कारण वर्ष के अधिकांश समय इस क्षेत्र में जल प्रवाह कम हो गया है; नदी के इस हिस्से में मुख्य रूप से मानसून के मौसम के दौरान और ऊपरी प्रवाह वाले जलाशयों से नियंत्रित रूप से छोड़े जाने वाले पानी के माध्यम से ही जल प्राप्त होता है; परिणामस्वरूप, तंजावुर क्षेत्र में रिवराइन कैप्चर फिशरीज सीमित तीव्रता के साथ केवल मौसमी ही रह गई है।

भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत, तमिलनाडु में रिवर रैंचिंग प्रोग्राम का कार्यान्वयन किया गया था, जिसके तहत मत्स्य संसाधनों को बढ़ाने, स्थानीय मत्स्य जैव विविधता को संरक्षित करने, कैच में वृद्धि करने और अंतर्देशीय मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा करने के लिए राज्य भर के नदी क्षेत्रों में 176 लाख उन्नत फिंगरलिंग्स छोड़ी गईं (जिसमें कावेरी नदी प्रणाली में 59.76 लाख अंगुलिकाएं शामिल हैं); इस स्टॉकिंग से कावेरी नदी प्रणाली में मत्स्य उत्पादन बढ़कर 220 टन होने की उम्मीद है, जिससे अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी और अंतर्देशीय मछुआरों की आजीविका को सहायता मिलेगी।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2015 से, तमिलनाडु के डेल्टा जिलों (तंजावुर, तिरुवारुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुरै और कुड्डालोर) सहित देश में मात्स्यिकी, अंतर्देशीय जलकृषि के समग्र विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में निवेश को काफी बढ़ाया है; तमिलनाडु सरकार ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, जलकृषि के तहत क्षेत्र विस्तार, सतत आजीविका को बढ़ावा देने और बायोफ्लॉक सिस्टम एवं री-सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर गहन जलीय कृषि के लिए (पीएमएमएसवाई) और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत कई गतिविधियां कार्यान्वित की हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय मछुआरों की परिचालन लागत को कम करने के लिए फिशिंग गियर हेतु PMMSY के तहत सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि डेल्टा जिलों के 355 लाभार्थियों को इनपुट सहायता और ताजे पानी की फिनफिश हैचरी के निर्माण, नए सीड रेयरिंग तालाबों, ग्रो आउट पॉन्ड्स के निर्माण, बायोफ्लॉक इकाइयों, RAS, ऑर्नामेंटल इकाइयों की स्थापना और मत्स्यन उपकरण की खरीद जैसी गतिविधियों के लिए PMMSY के तहत सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है। राज्य ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान डेल्टा जिलों में 450 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले पंचायत टैंकों में 9.00 लाख फिंगरलिंग्स के स्टॉकिंग की सुविधा भी प्रदान की है।

*****